



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 1990/अषाढ़ 27, 1912

No. 298] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 1990/ASADHA 27, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे फिर इलग संकरण के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

शक्तिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1990

मा. का. नि. 647 (अ):—ग्राम्यपत्र द्वारा जारी को गई निम्न-  
लिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है:—

यह: मूले, भारत के राष्ट्रपति, आर. वेस्टडार्मन हो अमृ. व. कॉमोर  
राज्य के राज्यपाल में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इन रिपोर्ट तथा  
युनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूशन सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है  
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का जातियां भारत  
के संविधान, जैसा कि वह उस राज्य पर लागू है, (जिसे इसमें हमके  
पासका "नियमन" कहा गया है) और अमृ. व. कॉमोर के संविधान (जिसे  
इसमें हमके पासका "राज्य संविधान" कहा गया है) के उपर्योग के अनुभाव  
महीने कलाया जा सकता है;

अब, इस मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा  
उस निमित्त मूले समर्थ बनाने काली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते  
हुए एतेहाय उद्घोषणा करता है कि मैं—

(ब:) संविधान और राज्य संविधान के प्रधीन उक्त राज्य की वरकार  
वे सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निर्दिष्ट अधिका-

उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति  
के रूप में स्वयं संवाधान हैं,

(ग) उद्घोषित करता है कि उक्त राज्य के विधान मंडल की  
प्रक्रियां संभव द्वारा प्रवाह उपरोक्त विधान के अधीन प्रयोक्तव्य  
होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और परिणामिक उत्तरांश करता है जो  
इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रसारी बढ़ाने के लिए मूले  
आवश्यक या वांछात्य प्रतीत होते हैं; अर्थात्—

(1) पूर्वोक्त के अनुसार, इन उद्घोषणा के अन्त (क) के  
आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों तथा शक्तियों  
का प्रयोग करने में मेरे द्वारा के राष्ट्रपति के  
रूप में, उन सीमा तक जिस तक मैं ठीक अपने, उक्त  
राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करता विविध;

(2) संविधान के तथा राज्य संविधान के निम्नलिखित उपर्योगों  
के प्रवर्तन को एवं द्वारा नियमित किया। जाता है,  
अर्थात्—

संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तु अन्य का उक्त  
भाग जिसने का संवंध गठित होता राज्य विवादक्षेत्र

के प्रति निर्देश न है, और उत्तर अनुच्छेद का दुसरा परन्तुक ;

गंविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उत्तर भाग जिसने का गंविध भारत के नियंत्रक और भविलेक्षा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के ममक प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के ममक रखे जाने से है ;

राज्य संविधान की धाराएँ 35 से 41 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), धारा 43 का उत्तर भाग जिसने का संबंध राज्य सरकार के मंत्रियों के बोच कार्य के बट्टारे से है, धारा 44, धारा 53 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का खंड (क), धाराएँ 54, 55, 56 तथा 57, धारा 58 के खंड (ब) और (ग) और उसका पहला परन्तुक, धारा 59, धारा 60, धारा 61 की उपधारा (2), जहाँ तक गंविध धारा 58 के खंड (ग) और पहले परन्तुक से तथा धारा 60 से है ;

धाराएँ 65, 66, 67, 71 और 72, धाराएँ 74, 75 और 76, धारा 77 की उपधारा (3) तथा (4), धाराएँ 85 से 88 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) और धारा 137 का उत्तर भाग जिसने का गंविध जारी रखित रिपोर्ट के राज्य के विधान मंडल के ममक रखे जाने से है ;

(3) संविधान में, और राज्य के राज्यपाल में, राज्यपाल के प्रति विस्तीर्ण निर्देश का अर्थ उत्तर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और संविधान में तथा राज्य के गंविधान में राज्य के विधान मंडल या उसके मदनों के प्रति, यथा नियमि, विस्तीर्ण लाएँ जाएंगा, और विस्तीर्ण राज्य के संविधान की धारा 91 में राज्यपाल के प्रति और राज्य के विधान मंडल भारा उत्तर दातां तथा निर्देश का अर्थ कमज़ोर राष्ट्रपति के प्रति और संबंध या उसके मदनों के प्रति निर्देश लगाया जाएगा ;

परन्तु इसमें यौं जोई बात राज्य संविधान की धारा 26 की उपधारा (1), धाराएँ 27 से 31 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), धारा 132, धारा 143 और द्वारा अनुसूची के पैरा 1 से 8 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उत्तरों पर भारा नहीं लानेगी और न राष्ट्रपति को इस खंड के उत्तरों (1) के अधीन, उस सीमा तक जहाँ तक है, उक्न राज्य के राज्यपाल के माओं कहो से नियारित करेगी ;

(4) संविधान में, या राज्य संविधान में राज्य के विधान मंडल के द्वारा बताए गए विभिन्नों या विभिन्नों के प्रति विस्तीर्ण लाए जाने वाले कानूनों का वरता है जो इस उद्घोषणा के अन्तर्गत नहीं द्वारा या राज्य की द्वारा दाता किया जाता है, तो उक्न के खंड (1) के उत्तरों (क) में विस्तीर्ण अवृ प्रधिनियम द्वारा राज्य के विधान मंडल की जैसी तरीका द्वारा हुए बनाए गए हैं, और जन्म 1 जनवरी 1977 का अधिनियम खंड अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्या 20) और साधारण खंड विनियम 147

(1897 का 10) का उत्तर भाग जिसना यज्ञ की विधियों पर नाहू होता है, ऐसे हिसे अधिनियम या विविध के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो पहले उत्तर यज्ञ के विधान मंडल का विविधत हो ।

नई दिल्ली,

विनायक 18 जुलाई, 1990

श्रावण,

राष्ट्रपति

[फ. सं. 5/11013/4/90--सी. पा. श्रावण]

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 1990

G.S.R. 647 (E):—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, R. Venkataraman, President of India, have received a report from the Governor of the State of Jammu and Kashmir and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India, as applicable to that State (hereinafter referred to as "the Constitution") and of the Constitution of Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as "the State Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I:-

- assume to myself as President of India all the functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the State Constitution;
- declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for

giving effect to the objects of this proclamation, namely:-

- (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
- (ii) the operation of the following provisions of the constitution and of the State constitution, is hereby suspended, namely:-

so much of the first proviso to article 3 of the Constitution as relates to the reference by the president to the Legislature of the state and the second proviso to that article; so much of clause (2) of article 151 of the Constitution as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

sections 35 to 41 (both inclusive), so much of section 43 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State, section 44, sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 53, sections 54, 55, 56 and 57, clauses (b) and (c) of section 58 and the first proviso thereto, section 59, section 60, sub-section (2) of section 61 so far as it relates to clause (c) of, and the first proviso to section 58 and to section 60; sections 65, 66, 67, 71 and 72; sections 74, 75 and 76, sub-sections (3) and (4) of section 77, sections 85 to 88 (both inclusive) and so much of section 137 as relates to the laying of the report with a memorandum before

the Legislature of the State, of the State Constitution;

- (iii) any reference in the Constitution and the state Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference in the Constitution and the State Constitution to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and in particular, the reference in section 91 of the State Constitution to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of sub-section (1) of section 26, sections 27 to 31 (both inclusive), section 122, section 143 and paragraph 1 to 8 (both inclusive) of the Second Schedule to the State Constitution or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

- (iv) any reference in the Constitution or in the State Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament, by virtue of this Proclamation or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Jammu and Kashmir General Clauses Act, 1977 (Act No. XX of 1977) and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as

applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi,  
The 18th July, 1990

R. VENKATARAMAN,  
PRESIDENT

[F.No. V/11013/4/90-CSR]

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1990

आदेश

मा. का. नि. 648 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश मर्यादित्यांक की सूचतार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:—

भारत के संविधान के प्रत्यक्षेत्र 356 के प्रतीत में द्वारा आज जुलाई, 1990 के प्रधारदृष्टि द्वारा जारी की गई उद्दोषण के घट (ग) के उपलब्ध (1) के अनुसरण में, मैं एन्डूडारा निदेश देता हूँ कि जम्मू व कश्मीर राज्य भूकार के सभी कृत्य तथा संविधान और जम्मू व कश्मीर के संविधान के प्रधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के प्रधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी गतिशील नियंत्रण राष्ट्रपति ने उक्त उद्दोषण के घट (क) के प्रयाप्त परम्परा संभान लिया है, राष्ट्रपति के प्रधीक्षण, निदेशन द्वारा नियंत्रण के प्रधीन रखते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा सो प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,  
विनाक 18 जुलाई, 1990

धार. वेंकटरामन,  
राष्ट्रपति

[फा. म. 5/11013/4/90—सी. एस. आर.]

नरेश चन्द्र,  
गृह मंत्रिय

## ORDER

New Delhi, the 18th July, 1990

G.S.R. 648 (E):—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 18th day of July 1990, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Jammu and Kashmir and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the Constitution of Jammu and Kashmir or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi.  
The 18th July, 1990.

R. VENKATARAMAN,  
PRESIDENT

[F.No. V/11013/4/90-CSR]  
(NARESH CHANDRA)

Home Secy.